

LOK SABHA

Wednesday, March 7, 1979/
Phalguna 16, 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of
the Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

* सीमेंट उद्योग में बिजुटी के तेल का उपयोग

* 233वीं प्रश्न सिंह ठाकुर :

श्री सुभाष झाहूजा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट उद्योग में कोयले के स्थान पर भट्टी के तेल का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सीमेंट के उत्पादन पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी साहू शास्त्री) (क) सीमेंट का उत्पादन करने वाले 9 एककों को जिन्हें तेल से चलने वाले प्रतिरिक्त उपकरण प्राप्त हो गए हैं, सीमेंट उत्पादन के लिए कोयले के कम संभरण के कारण कोयले की जगह अंशतः फरनेस शायत के प्रयोग की अनुमति दे दी गई है।

(ख) वे 9 एकक फरनेस शायत का प्रयोग करने अधिकतम प्रति मास 3,37,447 मी. टन का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

श्री प्रमन सिंह ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, भट्टी है तो भट्टी के तेल की कीमत बढ़ गई है, इस लिए सीमेंट उत्पादन के तेल से सीमेंट का उत्पादन होता में खर्चा बढ़ गया है और सीमेंट की कीमत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है तथा बाजार में सामान्य जनता इसे खरीदने से कथित है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सीमेंट उत्पादन के लिये कोयले के प्रयोग के स्थान पर भट्टी तेल के प्रयोग से सीमेंट की उत्पादन लागत में क्या कोई वृद्धि होती है? यदि हां, तो कितनी?

उपभोक्ताओं को इस वृद्धि से बचाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

क्या भट्टी तेल के उपयोग से सीमेंट की क्वालिटी में भी कोई अन्तर आता है?

कोयले की तुलना में भट्टी तेल के उपयोग से कोयले की दर तैक की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

3486 L.S.—1

श्री जगदम्बी प्रसाद शास्त्र: कीमत, कोयले की कमी के कारण ही फर्नेस शायत का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। आपकी पता होगा, पहले जब कोयले की प्राप्ति कई कारणों से नहीं हो रही थी और सीमेंट की आवश्यकता थी तो उस आवश्यकता को महसूस करते हुए फर्नेस शायत के उपयोग की अनुमति दी गई थी। फर्नेस शायत में जहाँ सीमेंट की उपलब्धि प्राइस मिल कर 130 रुपए तक हो जाती है वहाँ फर्नेस शायत की 1170 पड़ती है लेकिन जहाँ कोयला एक टन लगता है वहाँ फर्नेस शायत उसका प्राधा लगता है। फर्नेस शायत से कोयले के खर्च का मुकाबले में सीमेंट का जो काम बढ़ता है वह दुगुना होता है लेकिन ध्यान दि होल ज्यादा नहीं बढ़ता है। ध्यान दि होल 18 रुपए 53 पैसे प्रति टन बाय बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसलिए यह ज्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन आवश्यकता को देखते हुए इसकी जरूरत थी।

जहाँ तक काम की एफिलिएंसी का सवाल है, कोयले से फर्नेस शायत का काम ज्यादा अच्छा होता है परन्तु सीमेंट की क्वालिटी में कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री प्रमन सिंह ठाकुर क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाजार में सीमेंट की कीमत क्या है और कोयले की कमी के क्या कारण हैं?

श्री जगदम्बी प्रसाद शास्त्र: बाजार में सीमेंट की कीमत 20 रुपया प्रति बोरी है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि जो मकान परमिट पर बनाते हैं उनको कन्ट्रोल रेट पर सीमेंट मिलता है लेकिन जो गलत ढंग से मकान बनाते हैं और इस प्रकार से जो गलत ढंग से आवश्यकता बढ़ती है उसका बाजार भाव मैं नहीं बता सकता हूँ, हो सकता है उसका दाम बढ़ जाता हो।

कोयले की कमी की जहाँ तक बात है—नाबं इंडिया में बर्षा, बाढ़ के कारण बहुत सी माइन्स में पानी बसा गया था तथा बैंगनों की कमी की लेकिन अब यह संकट दूर हो गया है और अब कोयले की सप्लाई 70 परसेंट तक पहुंच गई है। जहाँ पर 700 बैंगन की आवश्यकता थी वहाँ पर 500 बैंगन की आपूर्ति की जा रही है।

श्री जगदम्बी प्रसाद शास्त्र: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सीमेंट इन्फ्लेट्री में कोल की जगह पर फर्नेस शायत पूरक किया जाता है—यह सुभाष देना चाहता हूँ कि कोल की जगह विमानाइट को भी पूरक

क्या जा सकता है। सुधारों के कच्चे विटिडेंट, बड़ी मात्रा में लिग्नाइट मिला है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कोल की जगह लिग्नाइट यूज किया जाये ?

श्री जनसम्बन्धी प्रस्ताव याचक : यह तो विचार करने के बाद की ही बातलाया जा सकता है कि लिग्नाइट यूज कर सकते हैं या नहीं।

श्री जनसम्बन्धी प्रस्ताव याचक : क्या आप इसका विचार करते ?

श्री जनसम्बन्धी प्रस्ताव याचक : इस के बारे में तो विचार करने के बाद ही पता लग सकता है।

SHRI DWARIKADAS PATEL. May I know from the hon. Minister whether in our country, many industries are suffering due to want of supply or shortage of coal? When Members ask questions the Energy Minister says that there was sufficient amount of coal.

MR. SPEAKER: He will not be able to answer about coal.

SHRI DWARIKADAS PATEL: I am coming to industry. There was sufficient amount of coal with them. But they do not get sufficient wagons and when they ask the Railway Minister for the supply of wagons, they are told that the railways have got sufficient number of wagons but for the short supply of coal, they have cancelled many goods trains and, as a result, the industries are suffering.

I would also like to know from the hon. Minister categorically as to what is the real position regarding the coal supply and, further, whether the Energy Minister is correct or the Railway Minister is correct.

MR. SPEAKER: I am sorry he will not be able to answer any one of your questions.

SHRI DWARIKADAS PATEL: The policy of the Janata Government is to shirk its responsibility.

MR. SPEAKER: He will not be able to answer.

U.S.S.R. offer of Heavy Water

*225. **SHRI PIUS+ TIRKEY:**
DR. BIJOY MONDAL:

Will the Minister of **ATOMIC ENERGY** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that USSR has recently offered to supply 200 tonnes of Heavy Water for Rajasthan Atomic Power Project;

(b) if so, the terms and conditions on which the offer has been made; and

(c) whether Government have rejected the offer and if so, the reasons thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, S

(b) and (c) Do not arise.

SHRI PIUS TIRKEY. Will the hon. Prime Minister be pleased to state whether it is correct that the supply of heavy water for Rajasthan Atomic Power Project is not forthcoming because U.S.A. demands the right of supervision? What are the alternative sources from which India plans to obtain heavy water if U.S.A. persists in its demand for inspection?

SHRI MORARJI DESAI: As I said, there is no proposal now of getting it. But, there was, in 1976, an agreement with Russia where they had agreed to supply 200 tonnes of heavy water. There, the safeguard has been accepted. The safeguard is that anything produced out of this should not be used for nuclear weapons or for any explosive devices. The safeguard is only for that purpose. And that was accepted in 1976.

SHRI PIUS TIRKEY: My second question is: will the hon. Prime Minister be pleased to state whether there is any government plan to discuss the matter with Shri Koryzhin in his forthcoming visit to India?